

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 192
No. 224] DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941 [N.C.T.D. No. 192

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

आदेश

दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण)

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सं. 02/2019-राज्यकर

फा. सं. 03(41)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/405.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का संग्रहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्भूत हुई हैं;

अतः अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (द्वितीय कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 है।
2. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उप-धारा (4) के स्पष्टीकरण में, “31 जनवरी, 2019” अंकों और शब्दों के स्थान पर “07 फरवरी, 2019” और शब्द रखे जाएंगे।
2. यह आदेश फरवरी 01, 2019 से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

ORDER

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES)

Delhi, the 3rd September, 2019

No. 02/2019-State Tax

F. No. 3 (41)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/405.—WHEREAS, sub-section (4) of section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AND WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under subsection (4) of section 52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Second Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. In section 52 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, in sub-section (4), in the Explanation, for the figures, letters and word “31st January, 2019”, the figures, letters and word “07th February, 2019” shall be substituted.
2. This Order shall come into force with effect from the 01st day of February, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)